मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

मोदी सरकार
(मुकेश अम्बानी की जेब में)

हवा-हवाई कॉलेज	3
किसानी बचाओ जंग	4
आरएसएस का जलवा	5
प्लास्टिक की पकड़	8

वर्ष 31 | अंक -29 | फ़रीदाबाद | 15-21 जुलाई 2018 | फोन : - 9999595632 | ₹ 2.50

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा एक हज़ार रेन हार्वेस्टिंग लगाओ छह साल पहले के एक सौ नब्बे बेकार पड़े हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के गिरते भूजल स्तर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर निगम के हरामखोर व रिश्वतखोर अधिकारियों को आदेश दिया है कि शहर में 1000 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम शीघ्रातिशीघ्र लगाये जायें ताकि बरसाती पानी भूजल स्तर को बढाये। इसके लिये निगम के सम्बन्धित अधिकारी ऐसे स्थान खोजने में जुट गये हैं जहां पर इनको बनाने से अधिकाधिक लूट कमाई हो सके।

सेक्टर 14 के एक पार्क में 5 वर्ष पूर्व बने ऐसे ही दो रेन हार्वेस्टरों के बारे में इस संवाददाता ने, तत्कालीन निगमायुक्त को बताया था कि इन दोनों में एक बूंद भी बरसाती पानी न कभी गया है और न कभी जा पायेगा क्योंकि वे बने ही इस ढंग से हैं। इस पार्क के तीनों ओर की सड़कें जब ऊंची हो गयीं तो उन पर खड़ा होने वाला बरसाती पानी बह कर पार्क में आने लगा। पार्क पानी से लबालब भर जाता। इसे सूखने में 2-3 दिन लगते।

जाहिर है वह सारा पानी भूमि में ही समाता था परन्तु यहां एक और समस्या आ गयी कि बरसाती पानी में घुल कर सीवर का सड़ा हुआ पानी अधिक आने लगा जिससे सारा वातावरण दुर्गंधमय होने लगा। अधिकारियों ने सीवर समस्या तो क्या ठीक करनी थी, पार्क में करीब 60 लाख की मिट्टी डलवा कर उसका लेवल इतना ऊंचा करा दिया कि अब सड़क का पानी सड़क पर ही खड़ा रहने लगा है।

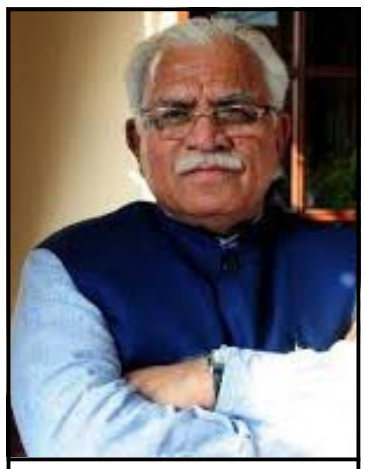

मनोहर लाल खट्टर : कुछ भी कह लो, कहने मे क्या जाता है मुख्यमंत्री के घर से!

मोहम्मद शाईन : जब से निगम का चार्ज मिला, बस बोलना ही बोलना तो काम रह गया है!

'मज़दूर मोर्चा' पहले भी कई बार लिख चुका है कि निगम द्वारा बनाये गये किसी भी रेन हार्वेस्टर से कभी भी एक बूंद पानी भूमि में नहीं उतर पाया है। जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत इस निगम ने सन् 2012 में करोड़ों की लागत से 190 रेन हार्वेस्टर शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाये थे। लगवाने वाले अधिकारियों का उद्देश्य केवल इस प्रोजेक्ट से लूट कमाई करने तक ही सीमित रहा। इसलिये ठेकेदार ने जैसे-तैसे ढांचे बना दिये और अधिकारियों ने बिल पास कर पेमेंट कर दी तथा अपनी वसूली करके फारिग हो गये। किसी हरामखोर अधिकारी या राजनेता ने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि करोड़ों रुपये की लागत से बने हार्वेस्टर किसी काम आ भी रहे हैं या नहीं।

अब खट्टर द्वारा 1000 नये रेन वाटर हार्वेस्टर बनाने का आदेश मिलने से निगम में बैठे भ्रष्टाचारियों की तो पौ बारह हो गयी। सन् 2012 में तो मात्र 190 के बनाने पर उनकी जो लूट कमाई हुई थी इस बार तो पांच गुणा अधिक होने वाली है। जब पहले बने हार्वेस्टरों को किसी ने नहीं देखा तो इस बार कौन चैक करने वाला है।

भू जल को रीचार्ज कर के उसका स्तर बढाने का सबसे बढिया प्राकृतिक साधन वर्षा और तालाब रहे हैं। शहर के सैंकड़ों तालाब पहले सीवर व गंद डाल कर सड़ाये गये और फ़िर बेच खाये गये अथवा अवैध रूप से कब्जा लिये गये। विदित है कि यह सब धंधा शासन व प्रशासन की मिलीभगत से ही संभव होता है। इसी के चलते एक ओर पीने तक के पानी के लाले पड़े हुए हैं और दूसरी ओर वर्षा के रूप में बरस रहा प्रकृति का अनमोल वरदान जलभराव व कीचड़ के रूप में जनता के लिये मुसीबत बनता जा रहा है। इसी पर फ़िर खट्टर जैसे नेता अपनी राजनीति करते हुये चिंता व्यक्त करने का मौका तलाश लेते हैं।

मलोट में कृषि समर्थन मूल्य का मोदी ड्रामा स्वामीनाथन की जगह मोदीनाथन डोज नाकाफी!

होडल (म.मो.) एमएसपी में सरकारी वृद्धि की दुर्दशा का ताज़ा तरीन उदाहरण होडल की मंडी में उपलब्ध है। इस वक्त वहां मूंग की फ़सल आई हुई है। मोदी सरकार ने एमएसपी में 2000 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि करके इसे 6975 रुपये कर दिया जो पहले 4975 रुपये प्रति क्विंटल था। लेकिन मंडी में किसान को मिल रहा है 4400 से 4700 प्रति क्विंटल का भाव यानी पुराने भाव से 200-500 रुपये कम। जिस किसान को उपज का पुराना एमएसपी सरकार नहीं दे पा रही उसको नया बढा हुआ कहां से दे पायेगी ?

पलवल तहसील के गांव औरंगाबाद के निवासी एवं भारतीय किसान यूनियन के नेता देशपाल चौहान ने बताया कि मोदी द्वारा बढाई गई एमएसपी की बात तो छोड़िये पहले से ही चल रही एमएसपी कभी किसान को नहीं मिली। इसी वर्ष जब वे अपनी गेहूं बेचने पलवल की मंडी में गये थे तो एमएसपी से 300 रुपये कम पर बेच कर आये थे, वह भी 4 दिन इन्तजार करने के बाद।

देश भर के किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिये कांग्रेस राज में स्वामीनाथन आयोगें गठित किया गया था। इसमें कहा गया था कि किसान की कुल लागत का डेढ़ गुणा दाम उसकी फ़सल का दिया जाना चाहिये। लागत निकालने के लिये भी तरह-तरह के हवाई फ़ार्मूले ही दिये गये। कुल मिला कर स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों ने किसानों के मन में बहुत आस जगा दी थी। जो किसान इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता वह भी इसे अपने लिये रामबाण औषधि समझने लगा।

स्वामीनाथन की जगह खुद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते सप्ताह कैबिनेट मीटिंग में कुछ फ़सलों के समर्थन मूल्य में 50 से 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा कर डाली। भाजपाई भांडों ने इसे **'मोदी आयोग'** की संज्ञा देते हुए स्वामीनाथन आयोग से तुलना कर डाली यानी अब स्वामीनाथन की सिफ़ारिशों की जरूरत नहीं रह जायेगी।

समर्थन मूल्य (एमएसपी) सरकार द्वारा निर्धारित किया गया वह मूल्य है जिससे कम पर किसान को अपनी फ़सल नहीं बेचनी पड़ेगी। यानी किसान को उसकी फ़सल का उतना दाम तो जरूर मिलेगा जो सरकार ने तय कर दिया है। परन्तु वास्तव में किसान को यह भाव कभी मिलता नहीं।

होता यह है कि किसान जब अपनी उपज मंडी में लाकर डाल देता है तो गिद्ध दृष्टि लगाये व्यापारी, आढती व सरकारी कर्मचारी उसको एमएसपी पर खरीदने आते ही नहीं। कई-कई दिनों तक उपज के ढेर मंडी में पड़े रहते हैं, किसान उनकी रखवाली के लिये रात-दिन पहरा देता है, फ़िर भी आवारा पशु तो उसमें मुंह मारते ही हैं, चोर उच्चके भी हाथ साफ़ कर जाते हैं। बारिश आ गयी तो फ़िर तबाही का कहना ही क्या।

इन हालात में किसान अपनी उपज को व्यापारी के मनमाने दामों पर बेचने में ही अपनी भलाई समझता है। इसके लिये भी आढती पूरा ड्रामा करता है। अपनी मिलीभगत को छिपाते हुये वह खरीदार व्यापारी को ऊंचे भाव पर मनाने का ड्रामा करता है। व्यापारी बहुत कम भाव बोलता है। फ़िर आढती एक बीच का भाव बोल कर 'जबरदस्ती' उसको बेचने की एक्टिंग करता है ताकि किसान यह समझे कि आढती ने बड़ी मुश्किल से व्यापारी को मना कर उसे कुछ बेहतर भाव दिलाया है। इससे भी भयंकर बात यह है कि इसी माल को फ़िर सरकार एमएसपी पर खरीद लेती है। बीच का मुनाफ़ा सरकारी कर्मचारी, आढती और व्यापारी के बीच बंट जाता है। अधिकांश मामलों में आढती ही व्यापारी भी होता है।

गत वर्ष किसानों की मांग पर हरियाणा सरकार ने खरीदी गयी फ़सल के चैक सीधे किसानों को देने की योजना बनाई थी। इस पर राज्य के व्यापारी रो पड़े और हड़ताल पर उतारू हो गये। इनकी शक्तिशाली लॉबी के सामने सरकार झुकी और खरीद के चैक सीधे किसान को न देकर आढती को ही देने की नीति कायम रही। यदि किसान को सीधे चैक मिलने लगता तो यह बीच की लूट एवं सेंधमारी का खेल समाप्त हो जाता।

एमएसपी तक भी न देने पाने का मामला केवल हरियाणा का नहीं पूरे देश का है। गुजरात-महाराष्ट्र के किसानों को मूंगफ़ली व कपास के निर्धारित भाव (एमएसपी) कभी नहीं मिल पाये। लहसुन, प्याज और आलू तो सरकार ने घोषणा करने के बावजूद नहीं खरीदे। हां राजस्थान व मध्यप्रदेश में चुनाव सिर पर देखते हुए बाजरे व ज्वार के भाव में गजब की वृद्धि कर दी मोदी ने। शायद इन बढ़े भावों की घोषणा मात्र से किसान बहकावे में आकर एक बार फ़िर से काठ की हांडी चढा दें।

मलौट (पंजाब) में मोदी किसान रैली कर अपनी पीठ बेशक थपथपा आये। देश का किसान तो उनकी थोथी घोषणाओं से भर पाया। लेना-देना खाक, मोहब्बत पाक!

विधायक सीमा की नौटंकी बेअसर, बिजली विभाग जस का तस

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में सुधी पाठकों ने पढ़ा था कि ग्रीन फ़ील्ड में किरकिरी के बाद, किस प्रकार विधायक सीमा त्रिखा ने बिजली विभाग के तमाम छोटे-बड़े अफ़सरों को सभागार में बुला कर अपनी हैसियत बताते हुये उन्हें ठीक से काम करने को कहा था। इसी हैसियत का प्रदर्शन करते हुये एन एच-2-3 के दो जेई बदल भी दिये गये।

लेकिन बैठक में अफ़सरों द्वारा दिये गये तमाम आश्वासनों के बावजूद स्थिति जस की तस है। न तो ग्रीन फ़ील्ड में कोई सुधार हुआ और न ही टाउन व सेक्टरों में। रात में 6से 8 घंटे बिजली गुल रहती है, शिकायत केन्द्र पर कोई फ़ोन तक नहीं उठाता। फ़ोन तो कोई तब उठाये न जब वहां कोई तैनात हो। इसका बेहतरीन उदाहरण सेक्टर 21 डी का है। शिकायत केन्द्र पर फ़ोन नहीं उठाया गया और लोग वहां पहुंचे तो ताला लगा पड़ा था। अब कर लो कोई क्या करेगा ? जलूस लेकर फ़िर रात में सीमा के द्वारे जाया जाय और फ़िर कुछ लोग हवालात में बंद हों या फ़िर चुपचाप जैसे-तैसे रात काट ली जाये।

दरअसल बिजली सप्लाई एक व्यवस्थागत प्रश्न है जिसे स्थानीय अधिकारी एक विधायक के कहने से हल करने की स्थिति में नहीं हैं, वे चाह कर भी इसे सुलझा नहीं सकते। इसके लिये सारे आधारभूत ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है। यह भ्रष्ट नेताओं के बस का नहीं क्योंकि बिना रिश्वतखोरी एवं कमीशनखोरी के विभागीय खरीद ये लोग कर नहीं सकते। अरबों रुपये की खरीद में करोड़ों का कमीशन नेता व अफ़सर अपना हक समझते हैं। इस चरमराये ढांचे को चलाये रखने के लिये आवश्यक स्टाफ़ के वेतन पर सरकार कुछ खर्च करना नहीं चाहती, बिजली चोरों को सरकार पकड़ नहीं सकती।

जाहिर है इन हालात में विधायक सीमा अधिकारियों को खरी-खोटी सुना कर और वे सुन कर अपना-अपना फ़र्ज अदा कर लेते हैं।

टंडन की दलाली में पनपते हैं गुनाह

फ़रीदाबाद (म.मो.) थाना एनआईटी क्षेत्र के अंतर्गत इन दिनों धंधेबाज़ माफ़िया टंडन की सरपरस्ती में बेखौफ़ होकर इलाके में नंगे होकर नाच रहे हैं। चोरी-छिपे नहीं बल्कि थाना एनआईटी से मात्र आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पर व कई धंधेबाज़ तो थाना एनआईटी से चंद कदमों की दूरी पर दिन-दहाड़े बीच सड़क सक्रिय देखे जा सकते हैं।

एनआईटी क्षेत्र में ऑन लाईन कैसिनो अवैध जुआ घर, अवैध शराब का धंधा, सट्टा, पर्ची, खुले में चलते देह व्यापार के अड्डे इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि टंडन की दलाली का धंधा चरम सीमा पर है। सूत्रों अनुसार टंडन इन धंधेबाज़ों से 15 से 20000 रुपये लेता है व टंडन की सरपरस्ती में सिर्फ़ एनएच 5 नम्बर में करीब-करीब एक दर्जन से अधिक प्वाईंट है। जिसके चलते टंडन थाना एनआईटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है।

एक तरफ थाना एनआईटी के एसएचओ हर दूसरे महीने बदले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थाना में तैनात एएसआई हरविन्दर व एक सब इंस्पेक्टर जो एनएच 5 ईंजीडे चौक पर टंडन के चेले गोपाल के अड्डे पर कर्मकांड करतेआसानी से देखे जा सकते हैं। धंधेबाज़ों की पूरी सूची है जो लोग टंडन की सरपरस्ती में पैटीक्राइम को बढावा देकर सीपी के सद्प्रयासों को पंकचर करने में जुटे हैं। विदित है कि उन छोटे गुनाहों की गोद में ही बड़े गुनाह पनपते हैं।